THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Kayamkulam Combined Cycle Power Project to be implemented by National Thermal Power Corporation (NTPC) has been accorded government approval based on funding through external commercial borrowings and internal resources of NTPC. However, in view of the availability of fund under World Bank time slice loan, the matter was pursued with them. World Bank has confirmed availability of fund in May, 1996 subject to a satisfactory solution of the mode of fuel transportation. NTPC has agreed to abide by the advice of the consultant appointed for the purpose. World Bank fund is expected to cover approximately 60% of the approved cost while the balance will be met by NTPC through commercial borrowings and internal resources.

(c) The award recommendations for the main plant turn-key contract for the project have the concurrence of World Bank. The award will be placed by NTPC after revised government approval is accorded to the project based on World Bank funding.

(d) First gas turbine (GT) unit of the project is scheduled to be commissioned within 30 months from the date of revised Government approval with subsequent GT unit(s) at an interval of 2 months each thereafter and the steam turbine (ST) unit in 42 months from the date of the Government approval.

Allocation of Tapti Gas to Pipavav Power Project

459. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had made a commitment to allocate Tapti Gas to Pipavav Power Project;

(b) if so, the reasons for non-fulfilment of the commitment; and

(c) by when Government are likely to supply Gas to Papavav Power Project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) A decision to allocate Tapti gas to the Pipavav Power Project was taken along with the decision to feed Gandhar gas into the HBJ pipeline.

(b) It was subsequently decided to allocate Gandhar gas to two power projects in Gujarat and to take Tapti gas to Hazira to meet existing commitments at Hazira and along the HBJ pipeline.

(c) The gas projected to be available in Gujarat is fully allocated. Supply of gas to Pipavav Power Project can be considered only when the availability of gas improves.

डोडा क्षेत्र में हत्या, आगजनी आदि की घटनाएं

460. श्री राघवजी:
श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर के डोडा क्षेत्र में लोक सभा चुनावों के बाद हत्या, आगजनी और लूटपाट की कितनी घटनाएं घटी हैं और इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) हत्या तथा अन्य अपराधों में अंतर्ग्रस्त व्यक्ति किन-किन संगठनों से संबंधित हैं; और

(ग) भविष्य में इन संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन): (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 1 जून से 30 जून, 1996 तक की अवधि के दौरान, विस्फोट, आगजनी, राकेट से हमलों/बेवजह गोलीबारी, आमने सामने की गोलीबारी, व्यवहरण इत्यादि की 82 घटनाएं हुई थी। आतंकवादी हिंसा की विभिन्न घटनाओं में 13 व्यक्ति मारे गए।

(ख) यह सूचित किया गया है कि ऐसी घटनाओं के लिए मुख्यतः पाक समर्थित आतंकवादी गुट हिज़्बुल मुजाहिद्दीन और हरकत-उल-अंसार जिम्मेवार है।

(ग) डोडा जिले में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ सम्मिलित हैः समय के साथ-साथ सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना, दूर दराज और सुभेद क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की 80 से अधिक चौकियां स्थापित करना, क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने और आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने के अभियान चलाने हेतु गहन गश्त लगाना, बड़ी संख्या में गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियां स्थापित करना, रामबन में अतिरिक्त पुलिस जिले का सृजन करना और पुलिस बल इत्यादि को सुदृढ़ करना। जिले में सुरक्षा की स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसकी सतत पुनरीक्षा की जाती है।

Proposal for Integrated Rural Sanitation received from Andhra Pradesh

461. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Andhra Pradesh had, on the 31st October, 1995, submitted a details project report on Integrated Rural Sanitation Project (1995) in Andhra Pradesh, with an estimated of Rs. 226 crores for the construction of 10 lakh household latrines in rural villages;

(b) if so, whether the Central Government have considered the proposal of the State Government; and

(c) if so, by when the Central Government are likely to provide funds to implement the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Considering that the total budget under Centrally Rural Sanitation Programme is Rs. 60 crores only, the State Government was requested to revise the project like adoption of low cost models of sanitary latrines, Information, Education and Communication (IEC) component for creation of felt need/demand, health education and awareness, in order to explore the possibility for external assistance also. This revised project is yet to be sent by the State Government.

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी संगठनों के साथ वार्ता

462. **श्री गोविन्दराम मिरीः क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कश्मीरी उग्रवादियों के साथ वार्ता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन उग्रवादी संगठनों के नाम क्या-क्या है जिनके साथ केन्द्रीय सरकार ने अब तक वार्ताएं की हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन): (क) से (ग) सरकार का दृष्टिकोण, बातचीत एवं विचार-विमर्श के द्वारा उन लोगों को प्रोत्साहित करने का है जिन्होंने हिंसा एवं टकराव का रास्ता छोड़ दिया है या इस रास्ते को छोड़ने के इच्छुक हैं तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शांति एवं प्रजातंत्र के सुदृढीकरण एवं बहाली के लिए काम करना चाहते हैं। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि बड़ी संख्या में वे लोग जो पहले उग्रवाद में संलिप्त थे, अब इससे विरत हो रहे हैं। उनमें से कुछ ने नए ग्रुप भी बना लिए हैं और राजनैतिक एवं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।

ऐसे कुछ व्यक्ति एवं ग्रुप जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर समस्या के स्थाई समाधान हेतु मंच, अवामी लीग आदि, सरकार के सम्पर्क में हैं और उससे बातचीत करते रहे हैं। इन चर्चाओं में अन्य बातों के साथ साथ विश्वास निर्माण संबंधी उपायों से जुड़े मुद्दों, निर्दोष नागरिकों को परेशान किए जाने, डराये धमकाए जाने और उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में कमी लाने के लिए उपाय करना, शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और अधिक